इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रतिवर्ष 40/रुपये

(आईएसओ 9001 : 2000 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 2 अंक सं. : 06 जनवरी 2010

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मुख्य घटनाएं-- 1
अर्थव्यवस्था-- 2
पूंजी बाज़ार--3
जिंस बाज़ार-- 3
बीमा --- 4
सूक्ष्म वित्तं--- 4
पारस्परिक निधियां---4
उत्पाद एवं गंठजोड़ --5
विनियामक के कथन -- 5
विशिष्ट घटनाएं ---7
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं -- 7
शब्दावली --- 7
संस्थान समाचार---8
बाज़ार की खबरें---8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएं

अनूठी पहचान संख्या बैंकों की अपने ग्राहक को जानिए नियमों में सहायता करेगी

निकट भविष्य में जनसंख्या के पर्याप्त खंड को अनूठी पहचान (UID) संख्या प्राप्त हो जाने के बाद बैंकों को नो फ्रिल्स खाते खोलने के लिए 'अपने ग्राहक को जानिए' (KYC) प्रक्रिया, ग्राहक के पूर्व-वृत्त की जांच का कार्य करने की आवश्यकता नहीं हो सकती। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन के लिए अनूठी पहचान संख्या के उपयोग पर आयोजित बैठक में हुए विचार-विमर्श को संकेत माना जाए, तो किसी व्यक्ति की अनूठी पहचान संख्या के सक्रिय हो जाने पर बैंक छोटे मूल्य वाले, नो फ्रिल्स खातों के लिए अपने ग्राहक को जानिए मानदंडों के अनुपालन की अनिवार्यता को समाप्त कर सकते हैं।

बैंक उस ग्राहक को भुगतान करने हेतु उत्तरदायी हैं, जिसकी धनराशि का गलती से भुगतान किया गया है

उच्चतम न्यायालय ने यह विनिर्णय दिया है कि बैंक उस ग्राहक को प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी हैं, जिसकी धनराशि खाता धारक के मूल हस्ताक्षर का सत्यापन किए बिना गलती से किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान कर दी गई है। विजया बैंक बनाम गुरनाम सिंह मामले में न्यायालय ने यह विनिर्णय दिया है कि बैंक सेवा में कमी का अपराधी था। न्यायालय ने बैंक की अपील खारिज़ करते हुए इस मुद्दे पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के निर्णय की पुष्टि कर दी। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि बैंक ने किसी धोखेबाज द्वारा प्रस्तुत किए गए चेक को सकारने तथा ग्राहक गुरनाम सिंह द्वारा किसी प्रकार के ओवरड्राफ्ट की सुविधा न प्राप्त किए जाने के बावजूद उक्त रकम के अलावा भी खाते में से अधिक रकम चुकाने में लापरवाही बरती थी।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मानव संसाधन परंपराओं पर रिपोर्ट मार्च में

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में मानव संसाधन (HR) प्रबन्धन परंपराओं के श्रेणी-उन्नयन की योजनाओं को ठोस रूप देने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की नियुक्ति की थी। डॉ. ए.के.

खंडेलवाल, भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति अपनी रिपोर्ट मार्च, 2010 तक प्रस्तुत करेगी, जिसमें वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अन्य मुद्दों के साथ ही जटिल खज़ाना कारबार, जोखिम प्रबन्धन, सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना प्रबन्धन, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों से सम्बन्धित लेनदेनों तथा वित्तीय उत्पादों के विपणन में कुशल व्यावसायिकों की भारी कमी को रेखांकित करेगी।,

कैथलिक सीरियन बैंक के नये प्रबन्ध निदेशक

श्री वी.पी. ईश्वरदास ने कैथलिक सीरियन बैंक के प्रबन्ध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। श्री ईश्वरदास, जिन्होंने श्री वेंकटरामन का स्थान लिया है, को तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है।

पंजाब नैशनल बैंक वर्ष 2013 तक 1 लाख गांवों का समावेश करेगा

देश के बैंक-रहित क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के अपने प्रयासों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक पंजाब नैशनल बैंक (PNB) 'नमस्कार परियोजना' में, जो शाखा-रहित बैंकिंग मॉडल के आधार पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी, वर्ष 2013 तक 1 लाख गांवों के समावेश को लक्ष्यांकित कर रहा है। पंजाब नैशनल बैंक ने वर्ष 2013 तक देश भर में 1 लाख संपर्क-बिन्दु बनाने की परिकल्पना कर रखी है। इसे स्पष्ट करते हुए पंजाब नैशनल बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री कामत ने कहा कि पंजाब नैशनल बैंक विभिन्न गांवों में 25,000 कियोस्क लगाएगा। प्रत्येक कियोस्क एक ऐसे कारबार संपर्की द्वारा संचालित होगा, जो निकटवर्ती गांवों के तीन अन्य कारबार संपर्कियों के साथ गंठजोड़ व्यवस्था करेगा तथा इन कियोस्कों का उपयोग लेनदेन करने के लिए करेगा।

इलाहाबाद बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

श्री जे.पी. दुआ ने इलाहाबाद बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का कार्यभार संभाल लिया है ।

मिस्त्री एचडीएफसी के नये मुख्य कार्यपालक अधिकारी

एचडीएफसी के उपाध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक श्री केकी मिस्त्री को 1ली जनवरी, 2010 से निगम के नये मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री मिस्त्री को 1 जनवरी, 2010 से उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। वर्तमान में संयुक्त प्रबन्ध निदेशक श्रीमती रेणु सूद करनाड को 5 वर्ष की अवधि के लिए निगम के प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

आईसीआईसीआई सिंगापुर में स्थानीय बैंक होने के लिए तत्पर

आईसीआईसीआई बैंक शीघ्र ही सिंगापुर में ऐसा पूर्ण-विकसित बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाली दूसरी वित्तीय संस्था बन जाएगा, जिसमें उसे एक स्थानीय बैंक की भांति ही शाखाएं खोलने, एटीएम लगाने, जमाराशियां स्वीकार करने और ऋण संवितरित करने की अनुमति होगी। सिंगापुर ने आईसीआईसीआई को देश में एक अर्हताप्राप्त पूर्ण बैंक (QFB) - एक ऐसी हैसियत जिससे उसे 15 शाखाएं और एटीएम केन्द्र खोलने की अनुमति होगी, के रूप में परिचालन करने की सिद्धान्तत: स्वीकृति दे दी है। सरकार द्वारा संचालित भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक को सिंगापुर में पहले से ही अर्हताप्राप्त बैंक के रूप में मान्यता प्राप्त है।

स्थानीय क्षेत्र बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का समर्थन

सरकार के वित्तीय समावेशन अभियान को आवेग प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक आगामी वर्ष से अधिक स्थानीय क्षेत्र बैंकों की अनुमति देना चाहता है। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक ने रघुराम राजन समिति द्वारा यथा संस्तुत इस प्रकार के और बैंकों को एक उपयुक्त विनियामक ढांचे की व्यवस्था कर लेने के बाद लाइसेंस दिए जाने के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया है। इनसे उन उत्पादों के बारे में स्थानीय जानकारी प्राप्त करने में सहायता की आशा की जाती है, जिनकी स्थानीय लोगों को आवश्यकता होती है। दो या तीन निकटवर्ती गांवों में परिचालन करने वाले स्थानीय क्षेत्र बैंकों की संकल्पना वर्ष 1996 के बजट में स्थानीय बचतों को संग्रहीत करने तथा उन्हें स्थानीय क्षेत्र में ही निवेश हेतु उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से की गई थी। उनसे ऋण की उपलब्धता में विद्यमान अंतर को मिटाने तथा ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों में संस्थागत ऋण ढांचे को बढ़ाने की आशा की जाती है।

बासेल के तहत बैंकों को अपेक्षाकृत कठोर पूंजी मानकों का सामना करना होगा

वर्ष 2012 से लागू किए जाने वाले अपेक्षाकृत कठोर विनियमनों के तहत बड़े बैंकों को कठिन स्थितियों के समक्ष संरक्षण के रूप में और लाभ अलग रखना होगा या यहां तक कि पूंजी जुटानी होगी। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति द्वारा प्रस्तावित नये नियमों में शीर्ष-स्तर की समझी जाने वाली आस्तियों पर तथा व्युत्पन्नियों एवं प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय से पैदा होने वाले जोखिम एक्सपोजर पर अपेक्षाकृत कठोर सीमाएं लागू की जाएंगी। बासेल समिति के अध्यक्ष श्री नौउत वेलिंक ने कहा है कि इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप बैंक अधिक लचीले होंगे तथा. बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली को अधिक सुदृढ़ता प्राप्त होगी। प्रतिपक्ष (counterparty) की ऋणपात्रता में कमी से जुड़ी प्रतिभूतियों के दैनिक बाज़ार मूल्य से होने वाली हानियों के लिए बैंकों पर पूंजी प्रभार लगाया जाएगा।

आवास कम्पनियों के पुनर्वित्तीयन पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने सफाई दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह विनिर्दिष्ट किया है कि आवास वित्त कम्पनियों (HFCs) को पुनर्वित्त के रूप में दिए गए बैंक ऋणों को उनके आवास वित्त कम्पनियों द्वारा दिए गए ऋणों के जितनी ही अवधि वाले न होने पर प्राथमिकता प्राप्त ऋण की हैसियत नहीं प्राप्त होगी। जुलाई, 2009 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को आवास वित्त कम्पनियों को व्यक्तियों को मकान की खरीद अथवा निर्माण हेतु पुन: उधार देने के लिए (केवल मार्च, 2010 तक) दिए गए उनके ऋणों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति प्रदान की थी, बशर्ते मंजूर किया गया आवासीय ऋण 20 लाख रूपये से अधिक न रहा हो। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार कछेक बैंक आवास वित्त कम्पनियों को 6 माह से लेकर 1 वर्ष के अल्पावधिक ऋण प्रदान कर रहे हैं और उन्हें प्राथमिकता प्राप्त अग्रिम के रूप में वर्गीकृत कर रहे हैं।

बैंक ऑफ बड़ौदा इस वर्ष 3000 अधिकारियों की भर्ती करेगा

कई एक आईआईएम और आईआईटी स्नातक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आजीविका आरंभ करने पर सक्रियता से विचार कर रहे हैं। श्री एम.डी. मल्या, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा के अनुसार फलत: बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ने पिछले वर्ष इन प्रमुख संस्थाओं से लगभग 50 अधिकारी भर्ती किए हैं। पिछले वर्ष बैंक ने व्यावसायिक संस्थानों और इंजीनियरिंग / कृषि महाविद्यालयों के परिसरों से लगभग 200 अधिकारियों की सीधी भर्ती की थी। उक्त अनुभव बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए इतना अच्छा रहा कि बैंक इस वर्ष इस मार्ग के माध्यम से 3000 और अधिकारियों को नियुक्त करेगा। श्री मल्या ने दावा किया है, "नये भर्ती हुए लोगों से प्राप्त योगदान अत्यधिक रहा है तथा सार्वजनिक क्षेत्र के वातावरण के प्रति उनकी अनुकूलनशीलता प्रशंसनीय है।"

अर्थव्यवस्था

37 % भारतीय गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करते हैं

प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉ. सुरेश तेंडुलकर की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञ दल के अनुसार प्रत्येक तीसरा भारतीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करता है। इससे भारत में गरीबी का प्रभाव-क्षेत्र कुल जनसंख्या का 37 % हो जाता है, जो इसके पूर्व लगाए गए अनुमान से 10 % अधिक है। राज्यों के स्तर पर उड़ीसा और बिहार निम्नतम स्तर पर हैं, जबकि नागालैंड, दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर में गरीबों की संख्या सबसे कम है। ग्रामीण जनसंख्या का 41.8 % प्रति व्यक्ति 447 रुपये मासिक आय पर जीवन-यापन करता है, जबकि 27.5 % लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजर करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के अनुपात के 28.3 % होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 25.7 % है।

अर्ध-वार्षिक समीक्षा के अनुसार अर्थव्यवस्था उच्च वृद्धि के मार्ग की ओर अग्रसर

सरकार की अर्ध-वार्षिक समीक्षा 2009-10 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के अधिक वृद्धि के पथ पर वापस आने के सुलक्षण दिखाई देते हैं, किन्तु इस पुनरुत्थान के साथ मुख्यत: खाद्य पदार्थों मे मूल्य-वृद्धि के कारण अपेक्षाकृत अधिक मुद्रास्फीति भी जुड़ी है। सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के इस वर्ष जुलाई में आर्थिक सर्वेक्षण 2008--09 में यथा पूर्वानुमानित 6.25 - 7.75 % की श्रेणी वाली ऊपरी सीमा में अथवा उससे भी अधिक रहने की संभावना है। पूंजी प्रवाहों की वापसी के परिणामस्वरूप अर्ध-वार्षिक समीक्षा के आधार पर अर्थव्यवस्था के एक बार पुन: मूल्य स्थिरता, विनिमय दर और पूंजी की गतिशीलता के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती से निपटने का प्रश्न खड़ा हो गया है।

पूंजी बाज़ार

मुद्रा वायदा क्रय-विक्रय आवर्त में नौ-गुणा उछाल

वर्ष 2008 के उत्तरार्ध में अनिश्चित शुरूआत के बाद शेयर बाज़ार में क्रय-विक्रय की जाने वाली मुद्रा व्युत्पन्नियों ने विदेशी मुद्रा के काउंटर पर क्रय-विक्रय (OTC) बाज़ार के समक्ष उनकी मुद्रा के मामले में मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। राष्ट्रीय शेयर बाज़ार (NSE) और बहु-जिंस तत्काल (spot) बाज़ार (एमसीएक्स -एसएक्स) में दिसम्बर, 2009 में इन लिखतों का औसत पण्यावर्त एक वर्ष पहले के स्तर से नौ-गुणा अधिक था। ये शेयर बाज़ार मुद्रा उत्पादों में जनवरी, 2009 में मात्र 2,400 करोड़ रुपये के मुकाबले 20,000 करोड़ रुपये से अधिक के औसत दैनिक आवर्त (ADT) वाला लेनदेन कर रहे हैं। हालांकि, जहां राष्ट्रीय शेयर बाज़ार और बहु-जिंस शेयर बाज़ार में तीव्र वृद्धि परिलक्षित हुई, वहीं बंबई शेयर बाज़ार में वर्ष 2009 की दूसरी छमाही में लेनदेन की स्थिति नगण्य रही। उक्त शेयर बाज़ार ने अपने मुद्रा वायदा प्लेटफॉर्म को नये शेयर बाज़ार अर्थात् यूनाइटेड शेयर बाज़ार में स्थानांतरित किए जाने की योजना की घोषणा की है।

जिंस बाज़ार

जिंस बाज़ार को बड़ा फ़ायदा

कृषि, सोना-चादी, धातुओं और ऊर्जा - सभी प्रकार की वस्तुओं में तेजडिया प्रवृत्ति की वापसी ने स्थानीय शेयर बाज़ारो, यथा मुंबई स्थित बहु- जिंस बाज़ार (MCX) और बहु-जिंस व्युत्पन्नी बाज़ार (MCDEX) तथा अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय बहु-जिंस बाज़ार (NMCE) के रोकड़ रजिस्टरों को खनका दिया है, जो खाद्यान्नों की बढ़ती कीमतों तथा सोने-चांदी, धातुओं, ऊर्जा जैसे उत्पादों में अस्थिरता के बीच शर्त लगाने

वालों (punters) और बचाव करने वालों (hedgers) की बढ़ती रुचियों का संकेत देता है। बहु जिंस बाज़ार में उसके औसत दैनिक पण्यावर्त में एक माह में ही 18 % का उछाल परिलक्षित हुआ , जिससे वह अक्तूबर में 20,700 करोड़ रुपये से बढ़ कर नवम्बर में 24.500 करोड़ रुपये हो गया, जबकि कृषि मंडी राषट्रीय जिंस व्युत्पन्नी बाज़ार (एनसीडीईएक्स) के पण्यावर्त में 48 % की जबर्दस्त वृद्धि देखने में आई और वह उसी अवधि में 4,600 करोड़ रूपये तक पहुंच गया। राष्ट्रीय बहु-जिंस बाज़ार (NMCE) के मुख्य कार्यपालक श्री अनिल मिश्र ने इस बात की पुष्टि की है कि उनका केन्द्र अपने पण्यावर्त में निरंतर वृद्धि दर्ज कर रहा है। अन्यत्र भारतीय महारथी भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम (MMTC) द्वारा प्रवर्तित आईसीएक्स ने प्रति दिन 10,000 से 12,000 लेनदेन करते हुए कुल छ: वस्तुओं में 2,307 करोड़ रुपये का अधिकतम पण्यावर्त दर्ज किया है।

बहु-जिंस बाज़ार (एमसीएक्स) ने प्रत्यक्ष लेनदेनों के लिए भावी सौदों की शुरूआत की

बहु-जिंस बाज़ार ने प्रत्यक्ष बिक्री और खरीद से सम्बन्धित मूल्य जोखिम में कमी लाने हेतु वास्तविक लेनदेन सुविधा के लिए एक भावी सौदा केन्द्र की शुरूआत की है। वास्तविक लेनदेन हेतु भावी सौदा केन्द्र में व्यापारी कोई वस्तु वास्तविक बाज़ार में खरीदता है तथा उस वस्तु की भावी संविदाओं को बेचता है, जबकि अन्यथा व्यापारी उस वस्तु को वास्तविक बाज़ार में बेचता है तथा उसकी भावी संविदाओं को खरीदता है।

जिंस बाज़ार ने किसानों की पहुंच को व्यापक बनाया : संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन

ऐसे समय में जब सरकार अनिवार्य वस्तुओं की कीमत से सम्बन्धित भावी सौदों के व्यापार के बारे में असमंजस की स्थिति में है तथा वह कृषि क्षेत्र की संवृद्धि को पुनरुज्जीवित करने की दिशा में प्रयासरत है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) के अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत और चीन में जिंस बाज़ारों ने कम जोत जैसी स्थानिक बाधाओं के बावजूद बाज़ार तक पहुंच को व्यापक बनाने में किसानों की सहायता की है। उक्त अध्ययन में यह बताया गया है कि जिंस बाज़ार बेहतर फसल उगाने और बेचने से सम्बन्धित निर्णय, भण्डारण सुविधा, श्रेणीकरण तथा प्रौद्योगिकी की आधारभूत सुविधा का कोटि उन्नयन करने एवं वित्त के अपेक्षाकृत सस्ते स्रोत तक पहुंच का विस्तार करने में किसानों की सहायता करते हैं। किसानों द्वारा इन बाज़ारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ मूल्य के प्रति उनकी अनाश्रयता (exposure) और संभाव्य उत्पादन जोखिमों में कमी लाते हुए उनकी विपणन एवं जोखिम प्रबन्धन क्षमता बढ़ाने में उठाया जा सकता है।

जिंस सूचकांक में निवेशकर्ता इस वर्ष दो गुणा अभिलाभ प्राप्त कर सकते हैं

तांबे, चीनी, सोने और तेल में आई मज़बूती के कारण जिंस सूचकांकों में निवेश करने वाले लोगों को इस वर्ष (अर्थात् 2010 में) दो अंकों में अभिलाभ प्राप्त होने की आशा है। हालांकि, तेल, जिसकी कीमतों में हाल के वर्षों में हुई तीव्र वृद्धि ने अन्य बाजारों में निराशाजनक कार्य-निष्पादन के बावजूद जिंस सूचकांकों को

बढ़ा दिया था, उसकी कीमतों के 70 % से अधिक होने के बावजूद इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादक नहीं था। गेहूं और अनाज की कीमतें वर्ष के दौरान कम रहीं, जिन्होंने सूचकांकों में बेहतर बढ़ोत्तरी को रोक लिया। बर्कलेज कैपिटल द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2009 के अंत तक पण्य सूचकांकों तथा अपेक्षाकृत अधिक कीमतों पर शर्त लगाने वाली केवल दीर्घकालिक निवेश रणनीतियां अपनाने वाली निधियों में 60 बिलियन डालर का रिकार्ड निधि प्रवाह हुआ। एक रिकार्ड स्तर तक निरंतर जमाव के बाद पिछले वर्ष वित्तीय संकट के दौरान अधिकांश वस्तुओं की कीमतों में गिरावट के परिणामस्वरूप बाज़ार के लड़खड़ा जाने के बाद जिंस निधियों में मुद्रा प्रवाह की शुरूआत हुई।

बीमा

कोटक लाइफ ने टैगलाइन की शुरूआत की

कोटक महिन्द्रा ओल्ड लाइफ इंश्योरेंस ने अपने नये ब्रॉण्ड टैगलाइन "फायदे का बीमा" की शुरूआत की है। उक्त उत्पाद को बाज़ार में उतारने से सम्बन्धित नया वक्तव्य प्रत्यक्ष और सुनिश्चित विधि से 'निवेशगत लाभ सहित जीवन बीमा' का संदेश देता है तथा इसके साथ ही एक ऐसे अभिनव विज्ञापन अभियान की शुरूआत की गई है, जो इस बदलाव को एक नवोन्मेषी और स्फूर्तिदायक विधि से संप्रेषित करता है। उक्त नव-प्रस्तुतीकरण अनुसंधान एवं पूंजी बाज़ारों के क्षेत्र में कोटक समूह की व्यापक शक्ति का निरूपण करता है।

भारतीय स्टेट बैंक को सामान्य बीमा उद्यम हेतु स्वीकृति

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को उसके सामान्य बीमा उद्यम के लिए क्षेत्रपरक विनियामक बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) से अंतिम अर्थात् आर3 अनुमोदन प्राप्त हो गया है। भारतीय स्टेट बैंक ने आस्ट्रेलिया स्थित इंश्योरेंस आस्ट्रेलिया ग्रुप (IAG) के साथ एसबीआई सामान्य बीमा नामक संयुक्त उद्यम का गठन किया है। इसके साथ ही बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पास पंजीकृत सामान्य बीमाकर्ताओं की कुल संख्या बढ़ कर 22 हो गई है।

छ: माह में जीवन बीमा उद्योग 18 % बढ़ा : प्रीमियम 21 % बढ़े

घरेलू जीवन बीमा उद्योग वर्ष 2009 के पहले छ: महीनों में 18 % बढ़े, जबकि पहले सात महीनों में उद्योग ने कुल प्रीमियमों (नये कारोबार और नवीकरण) में 21 % की वृद्धि की सूचना दी है। प्रीमियमों की रकम अप्रैल - अक्तूबर 2009 की अवधि में पिछले वर्ष की इसी अवधि के 99,310 करोड़ रूपये की तुलना में 1,20,000 करोड़ रुपये थी। जीवन बीमा परिषद द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार नवीकरण प्रीमियमों में

पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले लगभग 24 % की वृद्धि हुई, जिससे वे 73,922 करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंच गए, जबकि नये कारोबार के प्रीमियमों में लगभग 18 % की वर्षानुवर्ष वृद्धि हुई और वे 46,551 करोड़ रुपये रहे। नियमित यूनिट सम्बद्ध बीमा योजनाओं (ULIP) के कुल नवीकरण प्रीमियमों में 42 % की वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप वे पिछले वर्ष के इसी अवधि के 20,878 करोड़ रुपये से वर्षानुवर्ष बढ़ कर 29,738 करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंच गए, जबकि असम्बद्ध प्रीमियमों की रकम 44,214 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वर्ष के 38,897 करोड़ रुपये की तुलना में 14 % की वर्षानुवर्ष वृद्धि का संकेत करती है।

सूक्ष्म वित्त

एसकेएस माइक्रोफाइनैन्स ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ गंठजोड़ किया

एसकेएस सूक्ष्म वित्त ने भारतीय स्टेट बैंक और उसके समूह वाले दो बैंकों के साथ उनके पास अपने 600 शाखा लेखों के एकीकरण हेतु गंठजोड़ व्यवस्था की है। श्री दिल्ली राज, मुख्य वित्तीय अधिकारी, एसकेएस माइक्रोफाइनैन्स का कहना है "यह हमारे द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली देयता के पक्ष से सम्बन्धित नवोन्मेष है। इससे अंतिम स्तर के नकदी लेनदेनों में सुविधा प्राप्त होगी।" इस करार के एक अंग के रूप में हैदराबाद स्थित उक्त सूक्ष्म वित्त संस्था भारतीय स्टेट बैंक की 390, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की 150 और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर की 60 शाखाओं के साथ अपने खातों को एकीकृत करेगी। इसके पहले एसकेएस ने इसी प्रकार की सुविधा के लिए ऐक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के साथ गंठजोड़ व्यवस्था कर रखी थी।

एचडीएफसी ने एसकेएस माइक्रोफाइनैन्स के साथ गंठजोड़ व्यवस्था की

आवास वित्त क्षेत्र की महारथी एचडीएफसी लिमिटेड ने मध्यम आय वर्ग के किसानों और व्यापारियों को बंधक रखी जा सकने योग्य सम्पत्तियों पर उधार दे कर ग्रामीण खण्ड में प्रवेश करने हेतु एसकेएस माइक्रोफाइनैन्स के साथ गंठजोड़ व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के तहत एसकेएस माइक्रोफाइनैन्स उन आवासीय इकाइयों के विस्तार एवं सुधार हेतु ऋण उपलब्ध कराएगी जो भोजनालयों, किराने की दुकानों, पापड़ और अगरबत्ती निर्माण जैसी आय सर्जक गतिविधियों के लिए दोहरे उपयोग में आती है। एचडीएफसी प्रौद्योगिकीय सहायता तथा 10 करोड़ रुपये के निधीयन का पहला भाग उपलब्ध कराएगा। यह ऋण एसकेएस की 80,000 रुपये के एक औसत टिकट के आधार पर लगभग 1,250 सदस्यों का निधीयन करने में सहायता करेगा। कम से कम तीन वर्ष के ऋण इतिवृत्त वाले एसकेएस के सदस्य ग्राहक इन ऋणों के पात्र होंगे। उक्त योजना की शुरूआत आन्ध्र प्रदेश में एसकेएस की 10 शाखाओं के माध्यम से एक प्रायोगिक परियोजना के के रूप में की जा रही है। एसकेएस माइक्रोफाइनैन्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री सुरेश गुरुमणि ने बताया कि ब्याज दर 21 % सपाट होगी तथा ऋण की अवधि लगभग 3-5 वर्ष होगी।

पारस्परिक निधियां

शहरी पारस्परिक निधि निवेशकों ने ऑनलाइन अपनाया

80 % पारस्परिक निधि निवेशकों के भारत के 10 शीर्ष शहरों के निवासी होने के परिणामस्वरूप ऑनलाइन अनुप्रयोगों में, विशेषत: प्रविष्टि भार (entry load) पर रोक हटा लिये जाने के बाद बड़े पैमाने पर बढ़ोत्तरी हो रही है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट में वितरण प्रमुख श्री विनीत अरोड़ा दावा करते हैं कि "रोक हटा लिए जाने के बाद हमारे परिमाण में 45-50 % की वृद्धि हुई है। हम मासानुमास वृद्धि को पंजीकृत करते हैं। यह सुविधाजनक, पारदर्शी है और इसका लागत ढांचा भी न्यूनतम है। क्रय-विक्रय के अलावा, हम अनुसंधान सुविधा और उद्योग जगत की अद्यतन साख्यिकी भी उपलब्ध कराते हैं। निधि गृहों द्वारा ऑनलाइन माध्यम को बढ़ावा देने में पर्याप्त रुचि प्रदर्शित की जा रही है।" आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने हाल ही में पारस्परिक निधि के निवेशकों के लिए एक नये लागत ढांचे की घोषणा की है। उसने व्यवस्थित निवेश योजनाओं (SIPs) के लिए 30 रुपये के तथा 8 लाख रुपये से कम निवेश के लिए 100 रुपये के साकेतिक शुल्क की शुरूआत की है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट के पास संचयी पारस्परिक निधि धारिता के 8 लाख रुपये से अधिक होने पर निवेशक को किसी प्रकार के कमीशन का भुगतान नहीं करना पड़ता।

उत्पाद एवं गंठजोड़

सेन्ट्रल बैंक का प्रत्यावर्ती बंधक ऋण उत्पाद जीवन पर्यंत वार्षिकी उपलब्ध कराता है

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने "सेन्ट स्वाभिमान प्लस" जो उक्त बैंक से प्रत्यावर्ती बंधक ऋण का विकल्प अपनाने वाले वरिष्ठ नागरिकों को जीवन पर्यंत वार्षिकी का आश्वासन देती है, की शुरूआत करने हेतु स्टार यूनियन डाई-ची लाइफ इंश्योरेस के साथ गंठजोड़ व्यवस्था की है। सेन्ट्रल बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री एस. श्रीधर द्वारा यथापुष्ट समाचार के अनुसार उक्त उत्पाद वर्तमान उत्पाद (सेन्ट स्वाभिमान) का परिष्कृत रूप है। इस उत्पाद में किए गए सुधारों में से एक यह है कि विविध वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले वर्तमान प्रत्यावर्ती बंधक ऋणों पर अधिकतम 20 वर्ष के स्थान पर कोई वरिष्ठ नागरिक स्वयं अपने लिए जीवन पर्यंत भुगतान की सुविधा प्राप्त कर सकता / सकती है। देश में यह पहली बार है जब वरिष्ठ नागरिकों को प्रत्यावर्ती बंधक ऋणों पर किसी वार्षिकी उत्पाद को जीवन पर्यंत भुगतान मानने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

आईडीबीआई बैंक ने टोयोटा के साथ गंठजोड़ व्यवस्था की

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड ने वाहन वित्त उपलब्ध कराने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। उक्त समझौता ज्ञापन के अनुसार टोयोटा किर्लोस्कर मोटर और उसका व्यापरी (dealer) नेटवर्क वाहन - कारों और बहु-उपयोगी वाहनों के वित्तीयन को सुगम बनाने के लिए आईडीबीआई के साथ सहयोग करेंगे।

कारपोरेशन बैंक और रेलिगेयर के बीच समझौता

कारपोरेशन बैंक ने रेलिगेयर इंटरप्राइज की सहयोगी कम्पनी रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड के साथ उनकी सम्बन्धित शाखा / विपणन केन्द्र के माध्यम से संभाव्य लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) की पहचान करने के लिए तथा इस प्रकार के उद्यमों को वित्तीय सहायता / निभाव सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक समझौता ज्ञापन हस्तारित किया है।

टाटा एआईजी लाइफ ने चाइल्ड यूलिप की घोषणा की

टाटा एआईजी लाइफ ने बच्चों की शिक्षा के उद्देश्य से इन्वेस्ट अश्योर सुपरस्टार नामक एक यूनिट सम्बद्ध बीमा योजना की शुरूआत की है। इस योजना में माता-पिता (प्रस्तावक) की मृत्यु हो जाने की स्थिति में नामिती को बीमित रकम का भुगतान किए जाने के अलावा बीमा कम्पनी प्रीमियमों की माफी (WoP) की अन्तर्निहित सुविधा के माध्यम से भावी प्रीमियमों की व्यवस्था करेगी। परिपक्वता पर निधि का मूल्य नामिती को उपलब्ध कराया जाएगा।

ऐक्सिस बैंक और सीपीपी में गंठजोड़

सीपीपी असिस्टैन्स सर्विसेज ने ऐक्सिस बैंक के साथ रणनीतिक भागीदारी व्यवस्था की है। इस सहयोग के माध्यम से बैंक के कार्डधारक सीपीपी की कार्ड संरक्षण योजना, जिसकी कुछेक प्रसुविधाओं में खो जाने की सूचना, धोखाधड़ी से संरक्षण, आकस्मिक होटल एवं यात्रा सहायता, चाभी को जेब में रखने (Key fob) और अनुस्मारक स्टिकरों तथा मूल्यवान प्रलेखों का पंजीकरण शामिल है, का लाभ उठा सकते हैं।

इंडसइंड बैंक ने सौर-ऊर्जा चालित एटीएमों की शुरूआत की

इंडसइंड बैंक ने अपने हरित कार्यालय अभियान "हम और हरियाली" के एक अंग के रूप में मुंबई के पहले सौर-ऊर्जा चालित स्वचालित टेलर मशीन (ATM) की शुरूआत की है। उसने वातावरणपरक अनुसंधान एवं शिक्षा केन्द्र (CARE) के सहयोग से तैयार किए गए ग्रीन ऑफिस मैनुअल - ए गाइड टु सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज का भी विमोचन किया है। इंडसइंड बैंक ने इसके कार्बन फूटप्रिंट को कम करने के लिए एक व्यापक योजना भी तैयार कर रखी है। इस योजना के तहत आरंभ की जा रही कुछेक अन्य पहलकदमियां हैं

: थिन कम्प्यूटिंग, ई-पुरा भण्डारण (आर्चीविंग), ई-शिक्षण (लर्निंग), ई-रद्दी (waste) प्रबन्धन, कागज़-रहित फैक्स, ऊर्जा संरक्षण, हरित कार्यक्रम अपनाने के लिए प्रोत्साहनों के साथ सीएनजी कार और सहायक वित्त कार्यक्रम।

बिड़ला, भारतीय स्टेट बैंक ने सह-ब्रॉण्ड कार्डों के लिए गंठबंधन किया

आदित्य बिड़ला समूह ने सह-ब्रॉण्ड कार्डों की शुरूआत करने के लिए एसबीआई कार्ड के साथ गंठजोड़ व्यवस्था की है। आदित्य बिड़ला समूह की वित्तीय सेवाओं के मुख्य कार्यपालक श्री अजय श्रीनिवासन ने कहा कि इस गंठजोड़ व्यवस्था में समूह की कम्पनियां शामिल होंगी तथा यह इस बात को सुनिश्चित करेगी कि इस भागीदारी को सुदृढ़ बनाने में समूह की वित्तीय सेवाएं अपनी भूमिका सक्रिय रूप से निभाएं। सह - ब्रॉण्ड कार्ड किसी एअरलाइन या खुदरा बिक्री केन्द्र जैसी किसी विशेष फर्म से जुड़े क्रेडिट कार्ड होते हैं । उक्त प्रस्ताव से बारंबार यात्रा अंकों तथा विशेष छूट जैसी प्रसुविधाएं प्राप्त होती हैं।

एचडीएफसी बैंक ने क्रेडिट कार्ड की उप-सीमाएं लागू कीं

एचडीएफसी बैंक ने एक ऐसी सुविधा लागू की है, जिसके द्वारा कोई कार्डधारक योजक कार्ड, जो सामान्यतया मुख्य कार्डधारकों की पत्नी/पति को जारी किए जाते हैं, के लिए के सीमा नियतन को सुविधाजनक बना सकता है। कार्डधारक द्वारा किसी उप-सीमा का चयन न किए जाने पर प्रति विवरण चक्र ऋण सीमा के 100 % की चूक सीमा लागू होगी।

विनियामकों के कथन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूंजी अन्तर्वाह के मानदंडों को कठोर बनाया

भारत ने विदेशी पूंजी के अन्तर्वाह पर पुन: नियंत्रण लगाने का मन बना लिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशों से उधार लेने वाली कम्पनियों के लिए ब्याज दर की एक उच्चतम सीमा पुन: लागू कर दी है तथा विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय बॉण्डों (FCCBs) की पुन: खरीद सुविधा समाप्त कर दी है। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगामी 3जी सपेक्ट्रम नीलामी में किसी प्रकार की रुकावट न आए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दूरसंचार क्षेत्र की उन कम्पनियों के लिए जो विदेशी वाणिज्यिक उधार जुटाना चाहती है, पिछले वर्ष आरंभ की गई विशेष सुविधा को व्यापक आधार प्रदान कर दिया है। दूरसंचार क्षेत्र की कुछेक भारतीय कम्पनियों के समक्ष स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाने हेतु पर्याप्त वित्त के अभाव की बाधा उपस्थित हो गई है। सरकार जनवरी में सम्पन्न होने वाले 3जी स्पेक्ट्रम से कम से कम 35,000 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा करती है।

जमा की प्रवृत्ति के अनुरूप अल्पाविक ऋणों पर निर्भर करें : भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंको को अपने आप को दीर्घावधिक ऋणों में उलझाने के बजाय अल्प एवं मध्यम अवधि के लिए उधार देने पर ध्यान केन्द्रित करने की सलाह दी है। यह सलाह बैंकों के निधीयन के अल्पावधिक जमाराशियों से प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अत्यधिक लम्बी अवधि वाले परियोजना ऋण दिए जाने के कारण उनके समक्ष उपस्थित भारी आस्ति-देयता असंतुलन की स्थिति से उत्पन्न चिंता के अनुसरण में दी गई है। हाल ही में आयोजित एक बैठक में भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह कहा है कि चूंकि बैंकों की बहियों में मौजूद औसत देयता 1 से दो वर्ष की श्रेणी में होती है, वे अल्प से मध्यम अवधि (3 वर्ष) वाली परियोजनाओं को ऋण देने हेतु बेहतर ढंग से सक्षम हैं। फलत: इससे बैंकों को उनके आस्ति-देयता असंतुलन को सुधारने में सहायता प्राप्त होगी। बैंक दीर्घावधिक परियोजनाओं को केवल तभी उधार दे सकते हैं, जब उनकी बहियों में दीर्घकालिक देयताएं मौजूद हों। बैंकों के समक्ष उपस्थित होने वाली एक अन्य समस्या यह है कि वर्तमान विनियम जमाकर्ताओं को ब्याज दरों में वृद्धि होने पर उनकी सावधि जमाराशियों को तोड़ देने तथा उन्हें नये सिरे से अपेक्षाकृत अधिक दरों पर पुन: जमा करने की अनुमति प्रदान करते हैं।

सेबी ने नये ग्राहक - बैंकर दिशानिर्देश नियत किए

बाज़ार के सहभागियों में अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शिता और अनुशासन लाने के प्रयास में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशकों और (क्रय-विक्रय सदस्यों सहित) शेयर दलालों के बीच होने वाले लेनदेनों के सम्बन्ध में कुछेक अनिवार्य अपेक्षाओं की घोषणा की है। उक्त उपाय दलालों को ग्राहकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करता है। इन मानदंडों को कार्यान्वित करने की समय-सीमा 31 मार्च, 2010 है। शेयर दलालों के लिए यह आवश्यक है कि वे उनके साथ एक ऐसा करार करते हुए उन्हें पंजीकृत करें, जिसमें निवेशकों के वित्तीय ब्योरों दस्तावेज़ी साक्ष्य अर्थात् सदस्य-ग्राहक करार अथवा (किसी उप-दलाल के जुड़े होने की स्थिति में) त्रिपक्षीय करार, अपने ग्राहक को जानिए (KYC) फार्म तथा जोखिम प्रकटन प्रलेख आवश्यक रूप से शामिल हों।

2000 की आबादी वाले गांवों को मार्च, 2010 तक बैंकिंग सुविधा प्राप्त हो जाएगी : भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वाणिज्यिक बैंक इस वित्तीय वर्ष के अंत तक वित्तीय समावेशन का ध्येय पूरा करने के लिए योजना तैयार कर रहे हैं। तदनुसार, 2000 से अधिक की आबादी वाले सभी गांवों की वर्ष 2009-10 के अंत तक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच हो जाएगी। डॉ. सुब्बाराव ने कहा, "सामान्यतया वाणिज्यिक बैंक वित्तीय समावेशन को एक अनिवार्यता समझते हैं, किन्तु इस दुरूह लक्ष्य के पीछे अत्यधिक अवसर निहित हैं। हमारे लिए इस ग्रामीण बाज़ार में गहन पैठ बनाना जरूरी है, जो एक चुनौती और उसके साथ ही साथ एक अवसर भी है।"

राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता के लिए 10 % की अनिवार्य सीडिंग कायम रहेगी : इर्डा

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने यह विनिर्दिष्ट किया है कि देश में कार्यरत प्रत्येक सामान्य बीमाकर्ता द्वारा राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता - सामान्य बीमा निगम (GIC) को अर्पित की जाने वाली अनिवार्य रकम 10 % बनी रहेगी। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री जे. हरि नारायण ने इस बात की पुष्टि की है कि इस न्यूनतम स्तर को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान विनियमों के तहत सार्वजनिक और निजी, दोनों ही क्षेत्रों के घरेलू सामान्य बीमाकर्ताओं से उनके जोखिमों का 10 % अंश सामान्य बीमा निगम को अनिवार्यत: अर्पित किए जाने की अपेक्षा की जाती है। वर्ष 2007 से इस अनिवार्य स्वत्व-त्याग (cession) को 20 % से क्रमिक रूप से घटा कर 10 % कर दिया गया था। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का यह आदेश घरेलू सामान्य बीमाकर्ताओं में व्याप्त इस चिंता की पृष्ठभूमि में आया है कि 10 % के इस न्यूनतम स्तर को भी विशेषत: उस स्थिति में समाप्त कर दिया जाएगा, जब वैश्विक पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ संधि से सम्बन्धित बातचीत जारी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अशोध्य ऋण के प्रावधान से राहत प्रदान की

भारतीय रज़िर्व बैंक ने काफी बड़ी संख्या में बैंकों को राहत के रूप में उधारदाताओं को प्रावधान व्याप्ति अनुपात (PCR) को बढ़ा कर 70 % करते समय तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाली गई रकम को भी शामिल करने की अनुमति प्रदान कर दी है। दूसरी तिमाही में मौद्रिक नीति की समीक्षा में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से कठिन समय के लिए बेहतर सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए उस व्याप्ति अनुपात को बढ़ाने के लिए कहा था, जो अब तक अलग-अलग बैंकों के विवेक पर छोड़ रखा गया था। जारी किए गए दिशानिर्देशों में विनियामक ने बैंकों को प्रावधान अनुपात की गणना करते समय अनर्जक आस्तियों (NPAs) के लिए प्रावधान करने के अलावा उन अस्थिर प्रावधानों को भी शामिल करने की अनुमति दे दी है, जो टियर -II पूंजी में नहीं शामिल किए गए थे।

भारतीय रिज़र्व बैंक सक्रिय पूंजी प्रबन्धन की संभावना से इनकार नहीं करता

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने इस बात का उल्लेख करते हुए कि केन्द्रीय बैंक ने पूंजी के अन्तर्वाह के सम्बन्ध में मात्रा और मूल्य-आधारित नियंत्रणों का उपयोग किया है, उनके द्वारा दिए गए इस संकेत के बावजूद कि 'टॉबिन कर' कार्यसूची से निकाला नहीं गया है, पूंजी अन्तर्वाह में उछाल आने की स्थिति में सक्रिय पूंजी प्रबन्धन (जैसा कि 1996 में किया गया था) की संभावना से इनकार नहीं किया है। गवर्नर ने कहा है कि "पूंजी प्रवाह देश की वृद्धि संभाव्यता के आधार पर तथा कुछ हद तक कर अंतरपणन के कारण प्राप्त होते हैं। मध्य से लेकर दीर्घ अवधि तक हमारे लिए इन अंतर्वाहों को अवशोषित करना आवश्यक है। इस बीच हमारे लिए इसका अंशाकन करना जरूरी हो जाता है। मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति के आपूर्ति पक्ष को प्रतिबंधित करने के लिए अप्रभावी उपकरण होती है।" किन्तु मुद्रास्फीति के आपूर्ति पक्ष के स्थिर बने रहने पर वह मुद्रास्फीति से सम्बन्धित अपेक्षाओं को प्रभावित करेगा तथा मौद्रिक नीति को मुद्रास्फीति का शमन करना होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नकदी संचालन मशीनों के मानदंड निर्धारित किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नोट अधिप्रमाणन और उपयुक्तता निर्धारण मापदंडों के सम्बन्ध में दिशानिर्देशों का प्रारूप निर्धारित कर लिया है, ताकि इन मशीनों में नियमित अद्यतन की व्यवस्था की जा सके और उनमें नयी विशेषताओं वाली डिज़ाइनों / अध:स्तर / मूल्यवर्गों आदि का समावेश किया जा सके। ये मापदंड बैंकों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली नकदी संचालन मशीनों के लिए न्यूनतम मानक उपलब्ध कराएंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक के इन मापदंडों के अनुसार मुद्रा (करेंसी) नोट केवल तभी पुन: चालित अथवा पुन: जारी किए जा सकेंगे, जब वे प्रामाणिक और उपयुक्त के रूप में पुनर्मूल्यांकित कर लिए गए हों। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक जब कभी किसी विशिष्ट श्रृंखला को हटाने अथवा किसी विशिष्ट श्रृंखला को जारी करने या किसी विशिष्ट मूल्यवर्ग के नोटों को जारी करने का निर्णय ले, ये मशीनें प्रचलन से हटाए गए सभी नोटों को अनुपयुक्त नोट के रूप में अलग कर देंगी।

विशिष्ट घटनाएं

एक वर्ष बीत जाने पर भी मोबाइल बैंकिंग की गुंजार का इंतज़ार

पिछले वर्ष भारतीय रिज़र्व बैंक ने मोबाइल हैंडसेट का उपयोग करते हुए मुद्रा अंतरित करने तथा जमा शेष की जानकारी जैसी किसी भी अन्य मूलभूत बैंकिंग गतिविधि आरंभ किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया था। एक वर्ष बीत जाने पर शीर्ष बैंक ने स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि उक्त गतिविधि में यथापरिकल्पित रूप में प्रगति नहीं हुई है। मोबाइल का उपयोग करते हुए बैंकिंग सुविधा की प्राप्ति न्यूनतम, यहां तक कि 50 रुपये प्रति वर्ष या प्रति लेनदेन 2 रुपये अथवा 4 रुपये जितनी अत्यधिक कम लागत पर होती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति किस बैंक का चयन करता है। प्रौद्योगिकी भी महंगी नहीं है, क्योंकि बैंकिंग लेनदेन में यथा आवश्यक सबसे सस्ते हैंडसेट भी जावा-समर्थित होते हैं। इसलिए शुल्क और प्रौद्योगिकी की परवाह न करते हुए मोबाइल बैंकिंग के लिए हैंडसेट के उपयोग की जानकारी के अभाव और उसके साथ ही साथ लेनदेन सीमाओं का मोबाइल बैंकिंग में अभी तक प्रगति न हो पाने के कारणों के रूप में उल्लेख किया जाता रहा है।

साउथ इंडियन बैंक की विवाहित महिला कर्मचारियों को 4 वर्ष विश्रांति की सुविधा प्राप्त

एक दिशादायक कदम के रूप में त्रिशूर स्थित साउथ इंडियन बैंक (SIB) ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए एक चार वर्षीय विश्रांति का रोचक प्रस्ताव रखा है। इस कल्याणकारी उपाय का महिला कर्मचारियों, जो साउथ इंडियन बैंक के कार्यबल की एक-तिहाई हैं, द्वारा हार्दिक स्वागत किया गया है। साउथ इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. वी.ए. जोसेफ का कहना है, "यह एक

वैकल्पिक प्रस्ताव है । छ: माह पहले आरभ की गई इस विश्रांति सुविधा का विकल्प अब तक लगभग 30 महलिाओं ने अपनाया है।"

हर-मौसम के अनुकूल सड़कों से ग्रामीण आय दो गुनी : विश्व बैंक

विश्व बैंक के अनुसार भारतीय गांवों में हर-मौसम के अनुकूल सड़कों से ग्रामीण परिवारों की आय दो गुनी हो गई है, साक्षरता दर 10 % बढ़ गई है तथा जमीन की कीमतों में 80 % तक की वृद्धि हुई है। उक्त बैंक की वर्ष 2004 के लिए निर्मित ग्रामीण सड़क परियोजना रिपोर्ट में बैंक का निश्चयपूर्वक कथन है, "वर्ष 2000 में भारत के लगभग 8, 25,000 गांवों में से 40 % में हर-मौसम के अनुकूल सड़कों का अभाव था। अब सड़कों की उपलब्धता के परिणामस्वरूप परिवारों की आमदनियां 50 से 100 % तक बढ़ गई हैं, साक्षरता में 10 % की वृद्धि हुई है, जमीन की कीमतों में औसतन 60 से 80 % की वृद्धि हुई है।" बहु-पक्षीय उधारदात्री एजेन्सी भारत के ग्रामीण संयोजकता कार्यक्रम- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) में सहायता प्रदान कर रही है। यह हिमाचल प्रदेश, राजस्थान , झारखंड और उत्तर प्रदेश में परियोजनाओं को सहायता प्रदान कर रही है।

यू.के. चेकों को अलविदा कहेगा

दि यू.के. पेमेन्ट कौन्सिल ने कहा है कि भुगतानों को और कार्य-कुशल बनाने के लिए ब्रिटेन में वर्ष 2018 से कोई चेक जारी नहीं किया जाएगा और सकारा नहीं जाएगा। वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली उक्त कौन्सिल ने चेक द्वारा भुगतान किए जाने की 350 वर्ष पुरानी प्रणाली, जो उसके कथनानुसार "दीर्घकालिक दृष्टि से सीमावर्ती गिरावट से गुजर रही थी", को समाप्त किए जाने के लिए मतदान किया है। वर्तमान में अधिकांश भुगतान क्रेडिट या डेबिट कार्डों तथा प्रत्यक्ष नामे का उपयोग करते हुए किए जा रहे हैं, चेकों का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में तीव्र गिरावट आ रही है। कौन्सिल के मुख्य कार्यपालक श्री पाल स्मी ने बताया, "21वीं सदी में कागज़ द्वारा भुगतान करने की अपेक्षा कई एक और तरीके मौजूद हैं तथा अर्थव्यवस्था के लिए इसके प्रतिस्थापन से होने वाले लाभों का फ़ायदा उठाने का यही उपयुक्त समय है।"

परामर्श कक्ष ने क्रेडिट कार्ड से सम्बन्धित चूकें रोकने के उपाय तेज़ किए

कर्ज संकट से छुटकारा पाने के लिए भारतीय बैंकिंग आचार संहिता और मानक बोर्ड (BCSBI) के ऋण परामर्श स्कंध से संपर्क करने वाले लगभग 40 % उधारकर्ताओं की कई एक क्रेडिट कार्डों से सम्बन्धित बकाये की रकम कुछ हजार रुपये से लेकर कुछ लाख रुपये तक की श्रेणी में है। भारतीय बैंकिंग आचार संहिता और मानक बोर्ड के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो प्रत्यक्ष विपणन एजेन्टों (क्रेडिट कार्ड कारबार को आगे बढ़ाने के लिए बैंकों द्वारा नियोजित) के विपणन झांसे में आ गए थे, अपने ऋण-जाल से मुक्ति पाने के लिए उत्सुक थे। ऋण परामर्श की सुविधा अपना कर वे बैंकों के प्रति अपनी देयता को कर्ज की पुनर्संरचना के माध्यम से देय राशियों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा कर सकते हैं।

थोक जमाराशियों की दरें पुन: बढ़ीं

ब्याज दरों में वृद्धि की घोषणा करते हुए थोक जमाराशियों की ब्याज दरें बढ़नी शुरू हो गई हैं। कम से कम तीन बैंकों - यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) ने एक वर्ष की थोक जमाराशियों की दरें बढ़ा दी हैं। बाज़ार के सहभागियों के अनुसार नवम्बर, 2009 में 5-5.50 % की तुलना में इन बैंकों ने दिसम्बर में इन जमाराशियों पर 6.25-6.35 % देना आरंभ कर दिया। आम तौर पर 5 करोड़ रुपये से अधिक की जमाराशियों को थोक जमाराशियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लेहमान ब्रदर्स की विफलता के बाद जब वित्तीय संकट गहन हो गया, तो भारतीय बैंक संघ (IBA) ने बैंकों को थोक जमाराशियों की दरों को 6 % से अधिक न उद्धृत करने की सलाह दी थी। हाल ही में ऋण के कम उठाव और चलनिधि के अधिक हो जाने के फलस्वरूप थोक जमाराशियों की दरें घट कर खुदरा जमाराशियों से भी कम हो गई थीं, जिन्हें समस्यामूलक रूप में भी लिया जा रहा है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

जेड गणना (स्कोर) : ज़ीटा विश्लेषण लागू किए जाने से निकलने वाले गणितीय परिणाम। जीटा विश्लेषण निगमों (कॉर्पोरेशनों) के दिवालियेपन की पहचान करने का एक मॉडल होता है।

शब्दावली

टॉबिन कर :

वर्ष 1978 में नोबल पुरस्कार विजेता एक अर्थशास्त्री जेम्स टॉबिन ने पहली बार विदेशी मुद्रा लेनदेनों पर एक ऐसा कर लगाए जाने का विचार प्रस्तावित किया, जो सभी प्रमुख देशों द्वारा समान रूप से लगाया जाना अपेक्षित था। मुद्रा में उतार-चढ़ाव से सम्बन्धित सट्टेबाजी को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा में किए जाने वाले सभी लेनदेनों पर एक अत्यधिक छोटी रकम (0.5 % से भी कम) वसूल की जानी थी। जबकि दर पर्याप्त रूप से इतनी कम होगी कि जहां प्रतिफल अपेक्षाकृत अधिक हो, वहां लम्बी अवधि के निवेशों पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं डालेगी, वहीं वह विश्वभर में भारी मात्रा में मुद्रा लाने -ले जाने वाले सटोरियों के प्रतिफलों में कमी लाएगी, क्योंकि वे मुद्रा में होने वाले उतार-चढ़ावों में मामूली अंतर से भी लाभ कमाना चाहते हैं।

जिंस (पण्य) सूचकांक

पण्य सूचकांक विविध समूहों में से कृषि वस्तुओं का भारित तत्काल मूल्य सूचकांक होता है। उदाहरण के लिए, भारत में राष्ट्रीय जिंस व्युत्पन्नी बाज़ार (NCDEX) ने राष्ट्रीय जिंस व्युत्पन्नी बाज़ार पण्य सूचकांक के नाम से पण्य मूल्य सूचकांक की शुरूआत की थी, जो तेलों और तिलहनों, रेशों आदि जैसे विभिन्न समूहों के समावेश वाली 20 कृषि वस्तुओं का समान रूप से भारित तत्काल मूल्य सूचकांक है। भारत में आरंभ किया जाने वाला इस प्रकार का यह पहला सूचकांक है। तत्काल मूल्य सूचकांक के संघटकों पर आधारित राष्ट्रीय जिंस व्युत्पन्नी बाज़ार राष्ट्रीय सूचकांक भावी सौदों को भी प्रदर्शित करता है - जो किसी व्यक्ति के तत्काल दर पर भावी सौदों को खरीदने के इच्छुक होने पर अनिवार्यत: अंतरपणन-रहित मूल्य होता है। इस मूल्य का निर्धारण तत्काल सूचकांक के जितने ही भार वाले सूचकांकों के संघटकों के भावी सौदों के मूल्यों का पता लगा कर किया जाता है। वर्तमान में एफसीआरए (वायदा संविदा विनियमन अधिनियम, 1952), जिसमें भावी संविदाओं का अनिवार्यत: वास्तविक निपटान आवश्यक होता है, के अधीन भारत में सूचकांक भावी सौदों की अनुमति नहीं है।

संस्थान समाचार

26वां सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास स्मारक व्याख्यान 29 जनवरी, 2010 को सायं 5.30 बजे भारतीय स्टेट बैंक सभागृह, कॉरपोरेट सेंटर, भारतीय स्टेट बैंक, मादाम कामा मार्ग, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400 021 में आयोजित होगा। उक्त व्याख्यान डॉ. विजय केलकर द्वारा 'विनिवेश और निजीकरण की रणनीतियां' विषय पर दिया जाएगा।

भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत

- पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12
  पूर्व-अदायगी के बिना प्रेषित करने का लाइसेंस संख्या 15 / दक्षिण / 2010 -12
- मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रत्येक महीने की 25वीं और 26वीं तारीख को प्रेषित करें।

बाज़ार की खबरें

बाज़ार का आशुचित्र (रकम मिलियन रुपयों में)				
संकेतक	04 दिसम्बर 2009	11 दिसम्बर 2009	18 दिसम्बर 2009	25 दिसम्बर 2009
मुद्रास्फीति (%)	1.34 % (नवम्बर 2009)	1.34 % (नवम्बर 2009)	4.78 % (नवम्बर 2009)	4.78 % (नवम्बर 2009)
औसत चलनिधि समायोजन सुविधा प्रत्यावर्ती पुन: खरीद परिमाण	1,086,850	974,310	607,060	329,500
औसत चलनिधि समायोजन सुविधा पुन: खरीद दरें (%)	0	0	0	0
औसत पुन: खरीद दरें	2.72	2.46	2.74	3.03
10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति का प्रतिफल (%	7.5663	7.6320	7.6596	7.6689
1-10 वर्ष का अंतर (आधार अंक)	288	302	259	257
6 माह का वायदा प्रीमियम (%)	2.75	2.68	2.93	2.91
6 माह का अमरीकी डालर लिबोर (%)	0.49	0.46	0.46	0.43

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (CCIL) के न्यूज़लेटर, दिसम्बर, 2009

विनिमय दर
अमरीकी डालर / भारतीय रुपया नियत एवं अंतिम

46.80
46.70
46.60
46.50
46.40
46.30
46.20
4610

पूर्वान्ह 11.30 बजे
अपरान्ह 5.00 बजे
01-12-09 15-12-09 31-12-09

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI)

भारित औसत मांग दरें

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0

01/12/09 03/12/09 05/12/09 05/12/09 08/12/09 10/12/09 12/12/09 15/12/09 17/12/09 19/12/09 22/12/09 24/12/09 29/12/09

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर्स, मार्च 2010

श्री आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, श्री आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, 'दि आर्केड', विश्व व्यापार केन्द्र, 2री मंजिल, पूव स्कंध, कफ परेड, मुंबई - 400 005 से प्रकाशित।

संपादक : श्री आर. भास्करन

सेवा में

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
दि आर्केड, विश्व व्यापार केन्द्र, 2री मंजिल, पूर्व खण्ड, कफ परेड,
मुंबई - 400 005

टेलीफोन : 2218 7003 /

आईआईबीएफ विज़न जनवरी, 2010